

खाकी

जब पुलिस की जांच पहली बन जाती है

विकास नारायण राय

हरियाणा पुलिस ने कुछ ही दिनों पहले बड़े धूम-धड़ाके से केवाईसी (नो योर केस) ऐप लांच किया था, जिसने चारों ओर से प्रशंसा बटोरी। इस ऐप के जरिये आप कहीं से भी किसी केस की ताजा स्थिति का पता कर सकते थे। बेहद सुविधाजनक और पारदर्शी कदम! लेकिन जरा ठहरिये और तूल पकड़ रहे इस मामले पर भी गौर कीजिये।

मजदूर अधिकार संगठन की 23 वर्षीय नोदीप कौर को हरियाणा पुलिस ने 12 जनवरी को कुंडली, सिंगु बॉर्डर पर किसान धरना स्थल से उठाया। उन पर तीन मुकदमे दर्ज किये गए जिनमें हत्या का प्रयास और जबरन धन वसूली के अविश्वसनीय आरोप भी शामिल थे। उनके परिवार के अनुसार पुलिस हिरासत में उनके साथ मारपीट और यौनिक दुर्व्यवहार हुआ है। जबकि, किसान वकील कमटी के अनुसार नोदीप कौर के विरुद्ध दर्ज तीन में से एक भी एफआईआर हरियाणा पुलिस की साइट पर अपलोड नहीं की गयी है। तब, केवाईसी ऐप का क्या लाभ?

दरअसल, पुलिस अपनी संकटमोचक भूमिका को जब-तब वक्तव्यों से ही रेखांकित करती हुयी नहीं, कार्यकलापों से भी आलोकित करती मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा भी जांचने पर यह स्थिति पारदर्शी कम और पहली ज्यादा नजर आती है। जिन पर समाज को कानून की परिधि में रखने की जिम्मेदारी है वे स्वयं सबूतों को तोड़ने-मरोड़ने के आरोपों से प्रायः छिरे मिलें, ऐसा होना समाज और पुलिस दोनों के लिए दुखद है।

26 जनवरी को दिल्ली में किसान परेड के दौरान ट्रैक्टर सवार 25 वर्षीय किसान नवरीत सिंह की मृत्यु को प्रत्यक्षदर्शी शुरू से ही गोली लगने से हुयी मौत बता रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस इसे तेज रफ्तार



ट्रैक्टर के पुलिस बैरियर से टकरा कर पलटने से हुयी दुर्घटना मान रही है। आश्चर्यजनक रूप से ऐसी अप्राकृतिक मौत पर शव का जो पोस्टमार्टम दिल्ली में होना चाहिए था, वह रामपुर, यूपी में कराया गया। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में एसआईटी गठित करने की परिवार की याचिका का संज्ञान लिया है। नवरीत के परिवार द्वारा हासिल की गयी स्वतंत्र फॉरेंसिक राय के अनुसार, पहली नजर में नवरीत की चोटें दुर्घटना से लगी नजर नहीं आती। नवरीत के चेहरे पर गोली की एंटी और एगिजट के गन शॉट जैसे घाव हैं जो गोली के प्रवेश और निकासी से मेल खाते हैं।

इसी दिल्ली पुलिस ने इसी दिन लाल किले पर भारी उपद्रव और हिंसा के सामने गोली न चलाने का संयम दिखाकर व्यापक पेशेवर प्रशंसा बटोरी थी। उसे नवरीत के मामले में लीपा-पोती करने की क्या बाध्यता रही होगी? क्या राजनीतिक आकाओं के एजेंडा के साथ कदम-ताल करने की मंशा से?

पुलिस की जांच पर कानून भक्ति के बजाय राजनीति भक्ति का सबसे गंभीर आरोप भीमा कोरेगांव केस में सामने आने जा रहा है और वह भी एक स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के टेबल पर आ जाने से। अमेरिका स्थित विख्यात फॉरेंसिक लैब आर्सेनल के अनुसार आरोपी रोना विल्सन के कंप्यूटर में मिली जिन तमाम मेल के आधार पर वरवर राव, आनंद तेलतुम्बडे, सुधा भारद्वाज, फादर स्टेन

स्वामी, गौतम नवलखा इत्यादि मानवाधिकार क्षेत्र के बड़े नाम यूपा कानून में दो वर्ष से अधिक समय से देशद्रोह और प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के षड्यंत्र में जेलों में बंद हैं, वे रोना विल्सन के कंप्यूटर में एक मैलवेयर के माध्यम से प्लॉट की गयी थीं। यहाँ तक कि रोना का कंप्यूटर लगभग ढाई वर्ष से किसी ने निगरानी में रखा हुआ था।

आर्सेनल लैब ने सम्बंधित कंप्यूटर और मेल की यह जांच आरोपियों के वकीलों के कहने पर हाथ में ली थी। इनकी कॉपी कोर्ट के आदेश पर जाब्ता फौजदारी के नियमानुसार जांच एजेंसी एनआईए को आरोपियों को देनी पड़ी थी जिसे रोना विल्सन इत्यादि के वकीलों ने आर्सेनल लैब को स्वतंत्र जांच के लिए भेजा था। ध्यान रहे कि जाँच एजेंसी कॉपी उस सॉफ्टवेयर से तैयार करती है जिससे सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है। यानी आरोपी पक्ष की ओर से कॉपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लिहाजा, आर्सेनल लैब की रिपोर्ट की प्रक्रिया स्वीकृत मानदंडों पर खरी है और इसका संज्ञान भारतीय अदालतों में लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब होगा कि अब स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी उस सरकारी फॉरेंसिक लैब की होगी जिससे भारत सरकार की जांच एजेंसी ने जांच करायी थी।

जाहिर है, यदि भीमा कोरेगांव केस तमाम ख्यातिप्राप्त आरोपियों के विरुद्ध साजिश सिद्ध हुआ तो इससे आतंकवाद के विरुद्ध गठित भारत सरकार की जांच एजेंसी एनआईए की अंतर्राष्ट्रीय साख को भी धक्का लगेगा। लेकिन किसी को भूलना नहीं चाहिए, जांच एजेंसियों को भी नहीं, कि देश में मानवाधिकारों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। उनके भी हक में है कि वे पारदर्शी बनें, पहली नहीं।

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

व्यंग्य

मोदी की हमला थ्योरी

विष्णु नागर

मोदी जी की नवीनतम हमला थ्योरी (यह नया आविष्कार है-भाजपा की आईटी सेल का) भारत की छवि पर हमला (भारत को बदनाम करने की साजिश) भारत के योग पर हमला (भारत की चाय पर हमला) भारत के चाय मजदूरों की रोजीरोटी पर हमला (हमला ही हमला) साजिश ही साजिश (दुश्मन ही दुश्मन) जित देखें, तित हमला। यानी भारत के एकमात्र हितचिंतक ये ही बचे हैं। भारत के चौकीदार, भारत के सेवक, प्रधान सेवक, कवल यहा ह।



तो इस बार असम बंगाल तमिलनाडु, केरल आदि के चुनावों में हमला थ्योरी बेचेंगे (बिक गई तो इसे ही बेचते रहेंगे) वरना हिंदू मुसलमान तो है ही इनके तरकश का आखिरी तीर।

तो ये अब हमला- थ्योरी बेचेंगे। अभी कहा यह अंतरराष्ट्रीय हमला है (फिर कहेंगे कि विपक्ष इनकी मदद कर रहा है) विपक्ष देश के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है ये हवा में तीर चलाकर एक हवाई शत्रु को मारते रहेंगे, वोट बटोरते रहेंगे।

तो साहब इस हमला थ्योरी से सावधान (दिलचस्प यह है कि भारत की छवि पर हमला करनेवाले ही हमला-हमला चिह्न रहे हैं) ये संघ का सिद्धांत है। भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करो और कहो कि विपक्ष ऐसा कर रहा है (किसानों को मरने तड़पने के लिए छोड़ दो और कहो कि विपक्ष भड़का रहा है) अंतरराष्ट्रीय हस्तियां विरोध करें तो यह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है (यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का)!

विपक्ष सब कर रहा है, ये बेचारे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं (हाय हाय, कितने भोले हैं ये गरीब)। और भाइयो बहनो भारत की छवि को तो ये सड़क पर कीलें बिछाकर, बेरिकेड्स पर बेरिकेड्स खड़े करके बहुत सुधार रहे हैं न! (गोहत्या, लव जिहाद, नफरत के नये नये आविष्कार करके ये सुधार रहे हैं न! अर्थव्यवस्था को गड्डे में डालकर, प्रेस की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ करके, मानवाधिकारों का हनन करके, कुपोषण को बढ़ावा देकर ये भारत की 'छवि' सुधार रहे हैं। हमलावर ही हमला-हमला चिह्न रहा है। एक दिलचस्प कथा याद आ रही है (चोर को पकड़ने वालों में शामिल होकर चोर भी चिह्न रहा था -पकड़ो चोर, पकड़ो चोर।

राष्ट्रीय

ये क्रिकेट जिहाद नहीं, तुम्हारी सड़ी हुई मानसिकता का नमूना है

यूसुफ किरमानी

जाने-माने क्रिकेटर वसीम जाफर के साथ उत्तराखंड क्रिकेट संघ ने जो किया है वो इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत की इतना है। इससे वसीम जाफर और उस समुदाय का कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन दुनिया में जो जग हंसाई होगी, उसे फर्जी देशभक्त क्रिकेट प्रेमी अभी भी समझ नहीं पाएंगे। उत्तराखंड क्रिकेट संघ ने वसीम जाफर को एक सत्र के लिए अपना मुख्य कोच नियुक्त किया था, लेकिन अब उन पर मजहबी गतिविधि करने और मुस्लिम खिलाड़ियों को उत्तराखंड में बढ़ावा देने का आरोप लगने पर जाफर ने मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उत्तराखंड क्रिकेट संघ के कुछ पदाधिकारियों का कहना है कि वसीम जाफर को हटाया गया है। यह घटना ऐसे समय में हुई, जब भारतीय और पाकिस्तान मूल के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज से लेकर आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में अपने खेल से धूम मचा रहे हैं।

क्रिकेट की राजनीति

भारतीय क्रिकेट में राजनीति हमेशा से रही है। सुनील गावस्कर के बेटे रोहन, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को भारतीय टीम में शामिल करने को लेकर तमाम विवाद सामने आते रहे हैं। इसी तरह भारतीय क्रिकेट में क्षेत्रवाद भी खूब चला और चल रहा है, लेकिन यह राजनीति इतने निचले स्तर पर पहुंच जाएगी, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वसीम जाफर पर भाजपा नियंत्रित उत्तराखंड क्रिकेट संघ ने आरोप लगाया कि उन्होंने तीन बार क्रिकेट मैदान पर मौलवियों को बुलवाया।

खिलाड़ियों ने जब रामभक्त हनुमान की जय का नारा लगाना चाहा तो वसीम ने

सिख और बाकी धर्म के खिलाड़ियों का हवाला देकर ऐसा नारा लगाने से रोक दिया। इसकी जगह उन्होंने गो उत्तराखंड, कम ऑन उत्तराखंड नारा लगाने को कहा। इसके अलावा वसीम जाफर ने तीन खिलाड़ियों जय बिष्ट, इकबाल अब्दुल्ला और समद सल्ला को राज्य की टीम में शामिल किया। उत्तराखंड क्रिकेट संघ के आरोप इतने हास्यस्पद होंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। अगर खिलाड़ियों से कहा गया कि वो किसी धर्म विशेष का नारा न लगाकर उत्तराखंड पर नारा लगाएंगे तो इसमें बतौर मुख्य कोच वसीम जाफर का क्या अपराध है। इसी तरह मौलवियों को मैदान पर बुलाने के आरोप की पुष्टि के जवाब में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के खेलने के दौरान ड्रेसिंग रूम में नमाज पढ़ने, पूजा करने की घटना नई नहीं है।

अलबत्ता केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के नाम से नए संसद भवन की आधारशिला रखे जाने के दौरान किसी प्रधानमंत्री का पूजापाठ करके उसकी शुरुआत करना नई घटना है। फ्रांस से राफेल विमान लेते समय उस पर नींबू लटकाने, तिलक लगाने व नारियल फोड़ने और पूजा करने की घटना नई है, 26 जनवरी को राजपथ पर राज्यों की झांकी में यूपी की ओर से राम मंदिर का प्रोटाइप मॉडल पेश करना नई तरह की घटना है। उसी झांकी में बंगाल ने लैपटॉप लेकर बैठी युवती की झांकी पेश कर खुद को प्रगतिशील बताने का संकेत दिया था।

कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना
बेहूदा किस्म के आरोप लगाकर वसीम जाफर को हटाने की घटना दरअसल उसी राजनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए देश की मुख्य समस्याओं से ध्यान भटका कर उसका ध्यान हमेशा मजहबी कट्टरता के मामलों में उलझाए रखना है। देश के किसी न किसी कोने से हर हफ्ते मजहबी कट्टरता



खासकर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की घटनाओं को योजनाबद्ध ढंग से अंजाम दिया जाता है।

उत्तराखंड में भयानक प्राकृतिक आपदा आई। उसी के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम नाकामियां भी सामने आईं। किसानों का आंदोलन चल ही रहा है और आंदोलन को धार देने के लिए किसान संगठन तरह-तरह के आह्वान कर रहे हैं। उनकी तरफ सरकार के भोपू बने चैनलों का ध्यान न जाए, उसे वसीम जाफर जैसे मुद्दे थमाए जाते हैं। ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदा में उत्तराखंड की भाजपा सरकार केंद्र के भरोसे बैठी रही।

वहां के लोग जब राज्य सरकार को लेकर तमाम सवाल उठा रहे थे, उसी समय उन्हें बताया जा रहा है कि एक मुसलमान उत्तराखंड में क्रिकेट जेहाद कर रहा है।

गुरुवार 11 फरवरी को ट्विटर पर बाकायदा क्रिकेट जेहाद हैशटैग के नाम से अभियान चलाया गया, जिसमें वसीम जाफर को जमकर गालियां दी गईं। रामभक्त से पलभर में क्रिकेटभक्त बने इन फर्जी राष्ट्रवादियों को चंद पलों में उन तमाम मुस्लिम क्रिकेटर्स के नाम भूल गए जिनका योगदान अनगिनत भारतीय जीत में शामिल रहा है।

यह घटना मुसलमानों को सिलसिलेवार तरीके से हाशिए पर धकेलने की भी साजिश है। याद कीजिए जब यूपीएससी में ज्यादा संख्या में मुस्लिम बच्चे (हालांकि राष्ट्रीय अनुपात के मुकाबले नगण्य) आए तो संघी मीडिया ने यूपीएससी जिहाद अभियान चलाया, फिर जमीन जिहाद अभियान चला, उसके बाद लव जिहाद आया। अब इसे क्रिकेट जिहाद नाम दिया गया। बहुत साफ है कि जीवन के हर क्षेत्र को किसी न किसी जिहाद शब्द से जोड़कर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत के माहौल को जिंदा रखना है।

बड़े क्रिकेटर्स की चुप्पी

यह लेख लिखे जाने के समय तक एक भी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वसीम जाफर के समर्थन में नहीं आया। किसान आंदोलन को नजरअंदाज करके मोदी सरकार के लिए ट्वीट करने वाले इन बड़े नाम वाले खिलाड़ियों में से किसी ने भी वसीम जाफर के लिए आवाज नहीं उठाई, हालांकि इनमें से लगभग सारे मौजूदा नामी खिलाड़ी किसी न किसी समय वसीम जाफर के साथ खेल चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रणजी मैच खेलने का रेकॉर्ड वसीम जाफर के नाम ही है। खिलाड़ियों के हितों का दम भरने वाले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) तक ने वसीम जाफर के लिए दो शब्द नहीं कहे।

भारतीय क्रिकेट राजनीति से कभी अछूती नहीं रही। कांग्रेस के राजीव शुक्ल से लेकर भाजपा के स्व. अरुण जेटली,

अनुराग शर्मा और अब गृह मंत्री और देश के सबसे पावरफुल माने जाने वाले अमित शाह का बेटा जय शाह क्रिकेट में राजनीति के रास्ते ही आए हैं। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन वसीम जाफर की घटना देश में प्रदूषित मानसिक कट्टरता को बढ़ाने में खाद-पानी का काम करेगी। कहां हैं विराट कोहली एंड कंपनी जो मामूली बातों के लिए भी ट्वीट कर देती है, लेकिन इस घटना पर उन्होंने चूं तक नहीं की।

संघी मीडिया की सक्रियता

वसीम जाफर का मामला सामने आने के बाद संघी मीडिया भी निचली हरकतों पर उतर आया है। आर्गनाइजर डॉट आर्ग नामक वेबसाइट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें फर्जी वीडियो के सहारे बेहूदे आरोप लगाए गए हैं। इस साइट की रिपोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजामुल हक के हवाले से कहा गया है कि मैंने, सकलैन मुश्ताक और वसीम जाफर ने इंग्लैंड में गैर मुस्लिम खिलाड़ियों को इस्लाम अपनाने की दावत दी थी, हालांकि उस जहरीली रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि आखिर वो गैर मुस्लिम खिलाड़ी कौन-कौन थे और उन्होंने इस्लाम अपनाया या नहीं, इस पर वो रिपोर्ट मौन है। इसी तरह भाजपा आईटी सेल के लिए दिहाड़ी पर काम करने वालों की आर्मी इसी तरह की वाहियात रिपोर्ट का हवाला देकर नफरत की आग को और भड़का रही है।

अमेरिका में ब्लैक नागरिक जॉर्ज फ्लायड की हत्या पर भारत में जब सारे लोग मानवाधिकार कार्यकर्ता बनकर ट्वीट कर रहे थे और वही लोग कड़कड़ाती ठंड में किसानों पर बरसती लाठियों पर चुप थे, तो क्रिकेटर इरफान खान ने उस मुद्दे को उठाया था। संघी मीडिया हाथ धोकर इरफान पठान के पीछे पड़ गया था।

(वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक)